एस्बेस्टास खान का संचालन किया जा रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस खान से प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख मी० टन एस्बेस्टास निकाला जाता है जो देश का सर्वोत्तम एस्बेस्टास है।

परंतु इस खान में काम करने वाले 1500 आदिवासी श्रमिकों के लिए यह खान घातक साबित हो रही है। जब मजदूरों के संगठन यूनाइटेड माइन्स वर्कर्स यूनियन ने इस बात की जांच कराने की मांग की तो आठ मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया। मजदूरों को सिर्फ 7 से 10 रूपया दैनिक मजदूरी दी जाती है। उन्हें न आवास की सुविधा उपलब्ध है और नही पहाड़ी के ऊपर स्थित खान में पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के परिवहन की सुविधा। उनको बिजली भी नहीं दी गई है। उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। खान के अस्पताल में न तो एक्स-रे मशीन है और न वैज्ञानिक जांच की कोई अन्य सुविधा।

केवल इस खान में काम करने वाले मजदूरों की ही बात नहीं, इस खान की वजह से आसपास के आदीवासी गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न है। खान के पास ही क्रशर प्लांट लगा हुआ है जिसमें कच्चा एस्बेस्टास तोड़ा जाता है। एस्बेस्टास को इस संयंत्र के पास खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। खान और क्रशर संयंत्र से निकलने वाली धूल खान क्षेत्र और आसपास के आदीवासी गांवों में पहुंचती है जिससे अधिकाश आदिवासी लोग टी० बी० एवं कैंसर के शिकार होते हैं। देश के अन्य भागों में स्थित सभी सीमेंट और एस्बेस्टास काखानों में धूल से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी हानि को रोकने के लिए थर्मल प्रिसिपिटेटर लगाए गए हैं जबकि रोरी खान में ऐसी एहतियाती व्यवस्था नहीं की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के राबर्ड जान हैमिल्टन तथा सहायक महा निदेशक (खान), डा. बी. के. सेनगुप्त द्वारा यहां पर एक सर्वेक्षण किया गया। इससे भी स्पष्ट पता चला है कि खान से न सिर्फ खान में काम करने वाले मजदूरों को ही बल्कि आसपास के गांवों के अदिवासी लोगों के जीवन को भयंकर खतरा है। लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

13.25 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1983-84 - *contd.*

Ministry of Commerce and Department of Supply - contd.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up Demands for Grants relating to the Ministry of Commerce and Department of Supply. Shri Vyas was on his legs.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिटको के बारे में जिक्र कर रहा था। मिटको के अधिकारी बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिले रहते हैं और उनका सामान खरीदते हैं। जो गरीब लोग खान चलाते हैं, उनका सामान खरीदने वाला कोई नहीं है। इसीलिए, मैंने कहा था कि दस हजार मजदूर भीलवाड़ा जिले में मिटको की वजह से बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार और हमारी नेता श्रीमति गांधी की जो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट दिया जाए, वह पूरी नहीं होगी। लेकिन यह संस्था इस प्रकार से गड़बड़ी करके लोगों की रोजी-रोटी छीन रही है। इस प्रकार की अव्यवस्था की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने शुक्रवार

को भी जिक्र किया था और अब फिर कर रहा हूं कि मिटको पांच नम्बर के से नीचे का माईका नहीं खरीदती है । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भीलवाड़ा जिले में इससे नीचे के नम्बर का माईका खरीदा जाए । हमें कहा गया था कि पांच नम्बर से नीचे का माईका मिटको खरीदेगी । लेकिन, मिटको उसको नहीं खरीद रही है जिसकी वजह से सारी की सारी इन्डस्ट्री बेकार पड़ी हुई है । इसलिए, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मिटको के द्वारा इस प्रकार के माईका को खरीदा जाए तो इससे हजारों मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सकेगी । माईका के पेपर के बारे में मैं पिछले तीन साल से बराबर डिमान्ड्स पर बोल रहा हूं । माईका, बिहार, आन्ध्रा और राजस्थान में होता है । बिहार में आपने माईका पेपर इन्डस्ट्री को स्वीकृति दे दी है । राजस्थान के लिए पहले तो हमारा केस रिजेक्ट कर दिया गया । लेकिन जब हमने सरकार से रिप्रजेन्ट किया तो दुबारा केस को ओपन किया है । वहां पर जो माईका वेस्ट है, उससे कागज बन सकता है । इससे हजारों लोगों को रोजी रोटी मिल सकती है और फॉरेन-एक्सचेंज भी हम लोग कमा सकते हैं । इस प्रकार की एक इन्डस्ट्री भीलवाड़ा में अगर लग जाए तो माईका वेस्ट का उपयोग हो जाएगा और हजारों लोगों को रोजी-रोटी भी मिल जाएगी । इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है ;

अब मैं काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । कहीं पर तो ज्यादा पैसा देकर काटन खरीद लेती है और कहीं पर काटन की खरीददारी समय पर नहीं की जाती । इसकी वजह से बिचौलियों को मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है । यह संस्था इसलिए बनाई गई थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले पिछले साल टोटल प्रोडक्शन 80 लाख का हुआ था लेकिन सरकार ने केवल 10 लाख गांठें ही खरीदी । बाकी गाठें बिचौलियों के द्वारा खरीदी जायेंगी । बिचौलिए किस प्रकार की स्थिति पैदा करते है, यह सरकार से छिपा हुआ नहीं है । महाराष्ट्र में तो आपने सरकारी खरीद कंपलसरी बना दी है । दूसरे स्टेट्स में सी०सी०आइ० के अलावा कोई और संस्था नहीं है जो काटन को खरीदे और उसकी वाजिब कीमत लोगों को प्राप्त हो सके इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सारी की सारी काटन इस कारपोरेशन के द्वारा खरीदी जानी चाहिए ताकि किसानों को उसका पूरा पैसा मिल सके । आपका जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है, वह विदेशों से सामान मंगाता है । एडीबल ऑयल मंगाया जाता है क्योंकि यहां पर बहुत कमी है । करोड़ों रूपया इस पर खर्च करते हैं । यह चीज लोगों को ठीक प्रकार से मिल रही है या नहीं, यह भी देखना चाहिए । इतना करोड़ा और अरबों रूपया इस पर खर्च होता है । तो उस हालत में ऐडिबिल आयल की क्या व्यवस्था है । मैं एस० टी० सी० के बारे में कह रहा हूं, वितरण व्यवस्था के बारे में नहीं एस०टी०सी० इस सामान को मंगाती है, अरबों रू० का व्यापार करती है, क्या आपने उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी की है कि किस किस तरीके की गड़बड़ियां है? जब तक यह आप नहीं देखेंगे तब तक काम ठीक नहीं चलेगा। सारा इम्पोर्ट इसके जरिये होता है, और अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो देश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होता है । अतः आप इस ओर जरूर ध्यान दें ।

एक बात मैं टैक्सटाइल्स कमिश्नर के बारे में कहना चाहता हूं....,

MR. DEPUTY SPEAKER : You have already said that on the previous day, why are you repeating this ! It is already there in the proceeding. You have already spoken about Textile Commissioner. I have to stop you now. You are repeating the same thing which you have already spoken. Please conclude now.

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं । टेक्सटाइल्स कमिश्नर आफिस को कपड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एक आदमी को कितना कपड़ा मिलना चाहिये, क्या पोलिसी होनी चाहिये कपड़ा उत्पादन की इस सम्बन्ध में इस संस्था को कोई ज्ञान नहीं है । अपने यहां वूलन कपड़ा कितना बनना चाहिये इस देश में इसकी भी कोई जानकारी नहीं है । इस प्रकार का सफेद हाथी जिस पर करोड़ों रु० देश खर्च कर रहा है उसकी व्यवस्था को आपको देखना चाहिये । यह संस्था केवल पूंजीशतियों को लाभ देने के लिये नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को कपड़ा देने के लिये मजदूरों को ठीक से मजदूरी उपलब्ध हो, देश का उत्पादन बढ़े, इसी लिये यह संस्था बनायी गई है ।....

MR. DEPUTY SPEAKER : Now I am going to call the next speaker. I am not permitting you. Whatever he says will not go on record. Mr. Rajda.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : You have already taken 18 minutes. Please conclude now.

श्री गिरधारी लाल व्यास : आखिरी बात एन०टी०सी० के बारे में कहना चाहता हूं । आप कहते हैं कि इसकी मिलों में घाटा चल रहा है । तो 112 मिलों को घाटे में चलाते हुए भी जो कंट्रोल का कपड़ा लोगों को उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था आपका बड़े पेमाने पर करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में इन लोगों का समर्थन करता हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, five hours were allotted to this Ministry and we have already spent one hour 35 minutes. Now three hours 25 minutes are left. The Minister will have to reply to the discussion at 4.30 P.M. In the meanwhile, the Minister of State and the Deputy Minister will also have to intervene. The opposition has got one hour, the ruling party has got two hours 15 minutes and the Minister has got to reply at 4.30 P.M. Then, we have got to apply the guillotine also at 6 o'clock; that you know, since you know the rules. I will request all the Members that whatever time has been allotted to each party, shall be strictly adhered to. If everybody crosses that limit, some other Member from his own party will not have a chance to spaek. In that cases the Chair should not be blamed. Therefore, I would allot the time as it has been allotted and all Members are requested to stick to the time so that some Members can speak. Now, Shri Rajda, your party has been given 12 minutes.

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South) : I think I will abide by the time given to me.

MR. DEPUTY SPEAKER : Definitely. I know you are a strict, disciplined parliamentarian.

SHRI RATANSINH RAJDA : Thank you very much for the compliments.

MR. DEPUTY SPEAKER : After you finish your speech, the Minister of State will intervene and his intervention also will be as short as possible leaving it to the Minister finally to reply.

SHRI RATANSINH RAJDA : The Ministry of Commerce occupies a very pivotal position in the economic affairs of our country. The Finance Minister may be able to pick up the pockets of the common citizens but the entire monitoring of the economy generating the development of this

country squarely rests on the shoulders of the Ministry of Commerce. I welcome the new Commerce Minister. I am told, he is a man with administrative acumen and he has shown among the dark clouds on the horizon that he is a man who stands and falls by certain norms in public life. Among the Congress Chief Ministers we have dark clouds but here was the Chief Minister in U.P. When he could not manage or he thought that he has some moral responsibility, he resigned and that is something which has touched the common man in this country. With this view-point. I am going to tell him something.....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER : Are you going to tell him here also to resign ?

SHRI RATANSINH RAJDA : I would like him to see that the Commerce Ministry is result-oriented and I think he means business as far as Commerce Ministry is concerned, by bie formulation and guidance to country's trade policy and the policy on development and regulation of textiles and other export-oriented industries. Though you are playing a very pivotal role today, though you are presiding over the vast empire of the Commerce Ministry, I rise to state that today your empire is in doldrums. The Commerce Ministry is not running in the way it should run-that is my humble opinion. If he runs the affairs of the Commerce Ministry with highest speed and with utmost efficiency. I think we can boost up the economy of the country to a greater extent. Now, institutional infrastructure build up within the ambit of the Commerce Ministry has degenerated almost completely over the years.

It is necessary to rejuvenate it. An objective review of its working is needed together with the formulation of a constructive action plan for a fresh export drive. We are talking of export promotion but there is much lacuna in our drive.

STC has formulated ambitious plans, no doubt, to boost non-canalised exports during the last three decades but these plans are rarely implemented with any effectiveness. With the massive resources and power at its command, STC could have set an example in market development to the private sector but has unfortunately failed to do so, nor has the Export Promotion Council performed any better. Thers is lack of powerful result-oriented overseas marketing drive. That is the main difficulty and main lacuna in our drive with all our agencies that are working within the ambit of the Commerce Ministry. various commodity Boards are no better. Similarly, specialised functional agencies like Trade Fair Authority should be recast in a new mould to convert them into dynamic agencies. That can serve the cause of exports in a positive and purposeful manner. Having stated this, I would like to draw the attention of the hon. Minister to some of his agencies in the vast empire which are working with utmost inefficiency. Had it been merely the case of inefficiency, we could have stated that we must change one officer from here, we can being specialised advice, expertise, etc.

But it is not the case. As to Way the functioning of your Ministry is not shining out among the economic activities of our country, there are cogent reasons. I am going to give you certain concrete examples, as to why we are lacking in our effort and way the entire image of the Ministry is being tarnished Take the case of NTC. Take the case of MMTC. Everywhere we are below the targets. We never reached the target. There are lacunae. Day in and day out we hear in the press some scandal or the other. People of this country are hearing continuously such a thing. The question arises, what are we doing about those who are responsible for it or who are at the helm of affairs with the authority to revitalise the thing ? Why are they failing in their attempt ? Why are they not setting the House in order ?

I will give one example. Here is *Vyopar*, a Gujarati Daily. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER : Please do not interrupt.

SHRI RATANSINH RAJDA : He is a good friend of mine. Out of affection he is doing it.

I am going to present it to the hon. Commerce Minister. In *Vyopar* it has been stated that fraud has been committed in N.T.C. It is dated 5-1-1983.

> "Fraud to the tune of crores of rupees has been committed in N.T.C. Gujarat."

The officer who was assigned the task of investigating died and somebody else has been appointed. I would like to see a day when all such scandals and frauds come to an end, and our agencies work completely and fully.

Now I come to M.M.T.C. As far as the working of MMTC is concerned, I am sorry to say that the way it is working is something which is not only most unfortunate but also highly condemnable. The country has been frauded to the tune of crores of rupees for not only the inefficiency of the officers, but for the derelication of duty. I would say scandal worth crores of rupees is prevalent in M.M.T.C. The recent event that has taken place is an eye opener. The M.M.T.C. is the canalising agency for export of iron ore. It is a well known fact that the Corporation has miserably failed in achieving the target given to them for export of ore from India. In the last twelve months the target has been revised twice. Still the Corporation has not been able to meet it.

I am making this statement with full responsibility that the officials of the M.M.T.C. have been reported to be indulging in illegal practices of selling the high grade iron ore to foreign buyers at a lower price with a tacit understanding with the buyer for selling the price differential and detaining the part of that money outside the country. Something has happened. If the Hon. Minister wants, I am prepared to give him all the documents. Here was one of the gentlemen who was dealing with selling the Man-ganese Ore to foreign country. Naturally he could do it and deal through the agency of MMTC. He wrote to the MMTC that he has secured an order for 60,000 tonnes of Manganese Ore from abroad i. e. Czechoslovakia. MMTC wrote to him that the buyer be asked to negotiate with MMTC about the price.

The seller here or the gentleman wants to sell or the company or whatever it is, I would say 'A', because I would not like to name, at present. But if the Minister gets courage in both hands and is prepared to carry on the enquiry, many skeletons would come out from the cupboards of the MMTC. When the price was stated, the buyer was prepared to purchase at that price. And as suggested by the seller here, he approached the MMTC. The MMTC slept over it. The foreign buyer went on sending reminders : "Please tell us and quote us the price." Our officers did not quote any price. Is this not dereliction of duty ? I would say it is something more than that. Even when the reminders came, the price was not quoted and during all this time, the officers were touring the foreign countries. They were having tours. If the Minister enquires into the fact that how much orders they could secure for the country as a result of their tours, you would get the answer 'Nil'. So, again and again, the foreign buyer reminded the MMTC. What happened was, it was not given to the gentleman who had secured this order of 60 thousand tonnes. It was not even given to any other public sector undertaking. But then at a lower price, it was given to a private party in the private sector. Now, what is this ? This shows that there is something wrong in the kingdom of Denmark and unless we take stringent action, I think, all our agencies will bring a bad name to the Ministry of Commerce and its functioning.

With a view to put an end to this, I would like to give all those documents. I have got the documents. I have got the letter with me. I would submit them to the Minister himself so that he will look into the matter.

Apart from this, I would come to the question of rupee trade with U.S.S.R. Now, Sir, with U.S.S.R. and the East European countries, we are having rupee trade. Recently, a seminar was organised in Bombay and many intellectuals, experts and economists had participated and they have come to certain conclusion. They say that it is high time that our country must reconsider the entire question of rupee trade *de novo* and

the question should be whether our country is really and genuinely benefited through this rupee trade and whether there are some transfers through which some under-hand dealings are being played? Because of these things, they have come to a conclusion regarding the rupee trade with U.S.S.R. and other countries. Now, U.S.S.R. happens to be our great trading partner. U.S.S.R. is our great friend and we value the friendship of the U.S S.R. But at the same time if it comes to the conclusion that the method and mode of rupee payment is detrimental to the interests of our country, then, I think, it is high-time we should reconsider *de novo* the entire things. I have got all those details

There is an urgent need to solve the structural problem of Indo-Soviet trade on a permanent basis. This can be done only with the cooperation of the Soviet Union which should agree to export those commodities which are required for India's development. If this is not possible, it should agree to switch over to the trade based on covertible currency.

This is my plea. I do not know whether theGovernment would be allowing such a situation. If they do not allow such a situation, then many complications in our economy, in, future, are bound to arise.

The other day, we have read in the *Hindu*, dated 23rd, one article. They said, the way in which we have arrived at a decision to import crude oil to the tune of 2,50,000 tonnes from United States or Soviet Union is not good. You see the way in which we have done this despite our annual agreement with them. What does it indicate? Because the balance of trade is in favour of India--in our favour--we are pressurised to see that we purchase more crude oil from them.

All these things are over a short span of time. I think I have touched merely the fringe of the problem. There is much material which we could suggest to the Minister of Commerce. I think the Minister of Commerce is presiding over an empire which requires complete overhauling. Efficient handling must be there from top to bottom and if this is done, I think it will turn a corner in the history of the economy of our country.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the Minister of State will intervene.

It would be very short intervention.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : The dabate so far has been very interesting and a number of points have been raised focussing attention on certain aspects of the working of this Ministry. It is may privilege to intervene at this stage and touch upon some of the aspects referred to by Hon. Members in their speeches till now.

Certain points have been raised with regard to the export of cardamom as well as import of rubber. No doubt, cardamom export has declined in 1982-83 as compared to the previous year. But this is on account of fall in production in 1982-83 mainly due to drought and hence, the exports of cardamom during the year are also expected to be very much lower. In order to boost exports of cardamom, Government have granted cash compensatory support at the rate of 7% on all export of cardamom in consumer packs of up to 2 kg. The Board is also undertaking aggressive export promotion measures in the Gulf region. An outlay of Rs. 7 crores has been provided by the planning Commission for the development of cardamom plantation industry in the country during the Sixth plan period 1980-81 to 1984-85.

You will be happy to know that the country's production of rubber has been increasing steadily. With the diversification and improvement in our economy, consumption also is growing side by side. The increase in production over the years is in no small measure due to the operation of various development schemes by the Rubber Board. The result has been not only increased production in larger area, but also increased productivity of natural rubber. A major step in this direction is the implementation of the Rubber Plantation Development Scheme. This Scheme will operate up to 1993-94 and the total financial outlay for this Scheme is about Rs. 50 crores. An outlay of Rs. 36 crores has been approved by the

Planning Commission, for the development of the Rubber Plantation Industry during the Sixth Plan period for which the Planning Commission has set a production target of 2 lakh tonnes to be achieved by 1984-85.

Before deciding on import of rubber, a careful assessment is made by the Government of the estimate of production and demand in the country. If the gap between supply and demand is not covered, the rubber user industry will be seriously affected. It may be mentioned that, as far as possible, release of imported rubber will be made during the lean season. Whenever the situation so warrants, Government had not hesitated to ask STC to stop temporarily the release of imported rubber, mainly to safeguard the interests of the growers.

Even though no special reference directly has been made to leather exports, I would like to mention that Government's policy of encouraging valueadded leather products has started paying rich dividends. The leather sector is one which provides employment to weaker sections of the society. However, in recent years there has been a recession in international demand. We are taking all possible steps to support exports in this sector and it is expected that export of leather and its products again will pick up and exceed about Rs. 430 crores during the current financial year.

Reference has been made relating to the export of tobacco and the functioning of the Tobacco Board. I must mention that the Tobacco Board consists of 22 Members including the Chairman. The Board includes four representatives of growers and four representatives of dealers and exporters of tobacco products. Thus, the criticism that growers are not properly represented in the Tobacco Board, is not fully justified.

A reference has also been made for intervention of STC tobacco purchases. Out of the current year's production of 1,40,000 tonnes, about 1,11,000 tonnes have been purchased till 20th April, 1983. As many of you are aware, we have recently asked the STC to purchase lower grades of tobacco also. STC had to gear up its arrangements and has actually entered the market for exportable grades from 11th April, 1983. The purchases are still continuing. I thought that I should set the record straight on this matter and assure the Members that all possible action in this regard is being undertaken in the most expeditious manner.

I am also happy to mention that Government have taken a number of measures designed to increase trade, joint ventures and bilateral co-operation with the African continent. Some new trade offices of EPC, TDA, PEC have been opened in Africa and a number of trade agreements have been entered into. For the first time, all our heads of Missions in Africa got together to disscuss matters pertaining to our commercial economic co-operation with the African Continent as a whole, recently. At this Conference, 'An Africa Plan' for greater economic activitywith Africa has been endorsed.

In conclusion, I would like to assure the hon Members that all possible steps are being taken to increase our exports, diversify the products for export as well as our markets, in a manner fully consistent with our national economic priorities.

SHRI RATANSINH RAJDA : Very good.

MR DEPUTY SPEAKER : I am thankful to the Minister of State and I would request all the hon Members to follow the example of the Minister of State.

Now, Shri Krishna Kumar Goyal. Your party has been allotted 8 minutes. You should not take more than 10 minutes.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, में वाणिज्य मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा कि मंत्रालय में मंत्री

पद को उन्नत कर के आज कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उन्होंने भारत सरकार के स्टेटस को बढ़ाया है ।

गत वर्ष जब मैं इस डिमान्ड पर बोल रहा था, तो मैं ने कहा था कि यह बड़े खेद की बात हैकि कोमर्स मिनिस्ट्री को हैन्डिल करने के लिए केवल मिनिस्टर आफ़ स्टेंट दिया हुआ है जबकि इस के मिनिस्टर का स्टेटस फुल कैबिनट मिनिस्टर का होना चाहिए लेकिन में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज उनके सामने इस प्रकार की चुनौतियां हैं, विशव बाजार का जिस प्रकार का हाल है और जिस प्रकार की बैलेंस आफ़ ट्रेड और फारेन एक्सचेन्ज की स्थिति हमारे विपरीत होती चली जा रही है, उस के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है । मैं इस तरफ़ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1980-81 में हमारा ट्रेड डेफीसिट 5,849.58 करोड़ रूपये का था जो 1981-82 मैं जा कर 5,836.54 करोड़ रूपये हुआ और आप ने अपने विभाग की रिपोर्ट के अन्दर बताया है कि अप्रैल-दिसम्बर, 1982 में यानी 9 महीने के अन्दर यह ट्रेड डेफीसिट हमारा 4,059.96 करोड़ रूपये है और कम्पेयर करना चाहा है इतने ही समय को 1981 के अन्दर जो 4,109 करोड़ रूपये था और कहा है कि उस से हमारी परफार्मेन्स अच्छी है । मैं समझता हूं कि वह खराव है और आप इसपर गंभीरता से विचार करिये कि जो ट्रेड डेफीसिट 1978-79 के अन्दर केवल 1088.04 करोड़ रुपये था, 1979-80 में जो बढ़कर 2,636.82 करोड़ रुपये हुआ आज 9 महीने के अन्दर इस साल में यह 4060 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है।

14-00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय अगर आप विदेशी मुद्रा की स्थिति देखेंगे तो उसकी स्थिति और भी चिंताजनक पायेंगे । 1978-79 में हमारी विदेशी मुद्रा 5,219.9 करोड़ थी वह जनवरी, 1983 में 3,682.4 करोड़ रह गई । मैं समझता हूं कि यह अपने आप में गंभीर स्थिति है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है अगर आप 1980-81, 1981-82, 1982-83 और जनवरी 83 तक के बारे में देखें और इस पीरियड में आपने जो ड्राइंग्स की हैं उनको देखें तो आप पाएंगे कि ये जनवरी, 1983 तक 2,152.6 करोड़ के हैं । अगर हम इन ड्राइंग्स को भी मद्दोनजर रखें तो हमने वास्तव में जो विदेशी मुद्रा अर्जित की है, आयात नियति कर के जो हमारे पास बेलेंस रहता है वह 1,529.8 करोड़ रुपये का रह जाता है । मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर प्रश्न है । हमने आई०एम०एफ० से लोन भी लिया है । इन सब के कम्प्लीकेशंस क्या हुए ? इस पर हमसब को विचार करना है ।

हमारे यहां जो फारेन एक्सचेंज बाई वे आफ इम्पोर्ट और बाई वे आफ एक्सपोर्ट बचा, अगर हम ड्राइंग्ज को निकाल दें तो वह 1529.8 करोड़ रुपये का रह जाता है । इसके साथ ही में कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से हम अपने बेलेंस आफ ट्रेड को केलकुलेट कर रहे हैं, उसमें मैं सोचता हूं कि हम उस रूपी ट्रेड को भी शामिल कर रहे हैं, उन ईस्टर्न यूरोपियन कन्ट्रीज के साथ और मास्को के साथ होने वाले रूपी ट्रेड को भी शामिल कर रहे हैं जिसने हार्ड करेन्सी में हमारे ट्रेड को छिपाया हुआ है । जो हमने रूपी ट्रेड किया, उसका जो रुपया हमारे पास आया, में समझता हूं कि वह हमारे बेलेंस आफ ट्रेड की स्थिति को छिपाता है । हमारा रूपी ट्रेड मास्को या अन्य कन्ट्रीज से कुल विश्व व्यापार का एक चौथाई है । अगर हम यह एक चौथाई रूपया जो हमारे पास रूपी ट्रेड के माध्यम से आया, माइनस कर दें तो हमारे बेलेंस आफ ट्रेड

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

की जो कि बाई वे आफ इम्पार्ट और एक्सपोर्ट स्थिति है, वह हमारे सामने एक निराशजनक और भयानक रूप में आयेगी। इसलिए में आशा करता हूं कि वाणिज्य मंत्री जी इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि रूस से हमारी मित्रता है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मास्को ने जिन कठिनाइयों में हमारा साथ दिया वह हमारी और उसकी मित्रता का द्योतक है। वह आज भी विश्व की कठिन परिस्थिति में हमारे साथ मित्रता निभा रहा है। लेकिन मित्रता एक अलग चीज़ होती है और व्यापार एक अलग चीज़ होती है मित्रता और व्यापार को अलग अलग तोलना पड़ेगा। इस नाते में कहना चाहता हूं कि, मास्को या विश्व के साथ जो हमारा ट्रेड हो वह उसी आधार पर हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज हमे बेलेंस आफ ट्रेड के बारे में विचार करें - यह ठीक है कि हमारा बेलेंस आफ ट्रेड फेवरेबल है - लेकिन ट्रेड फेवरेबल कहां माना जाता है। यह फेवरेबल माना जाता है इन टर्म्स आफ हार्ड करेंसी। अगर हार्ड करेंसी के माध्यम से यह फेवरेबल हो तो यह बेलेंस आफ ट्रेड फेवरेबल माना जाएगा। अगर हम रूपी ट्रेड को साथ ले कर चलें और कहें कि बेलेंस आफ ट्रेड हिन्दुस्तान के पक्ष में है तो यह ठीक नहीं है। रूपी ट्रेड कभी भी सरपलस नहीं होना चाहिए, चाहे यह किसी भी कन्ट्री से चल रहा हो।

PROF. N.G. RANGA (Guntur): In what way and to what extent, is it disadvantageous to have surplus trade balance with Russia and Eastern Europe? We must know that. It is no use in saying that.

SHRI KRISHNA KUMAR Goyal: I am coming to that.

उपाध्यक्ष महोदय हमारा जो रशिया से ट्रेड है उसमें 1145 मिलियन रूबल्स अभी तक हमारे सरपलस एक्यूमुलेट हो गये हैं जो लगभग 12 मिलियन रूपीज के बराबर होते हैं। इसके बारे में आप यह देखें कि यह जो ट्रेड हो रहा है उसके बारे में कोई भी यह नहीं जान पाता कि यह किन टर्म्स के आधार पर और किस प्राइस के आधार पर हो रहा है।

मास्का और इंडिया का ट्रेड चल रहा है। 2.5 मिलियन टन क्रूड आयल का एग्रीमेंट किया गया है। मैं वाणिज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं....।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a secret agreement. It is an agreement like any other agreement with other countries.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: One may or may not agree but these are my views.

दो भाइयों में भी व्यापार नियमों के आधार पर ही होता है। आइल की कीमत ओपेक प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस के आधार पर फिक्स होती है। 2.5 मिलियन टन का रशा से एडीशनल एग्रीमेंट किया गया है। सुना है कि इस एग्रीमेंट पर साइन एयरपोर्ट पर हुए हैं। मिनिस्ट्री में इस पर झगड़ा चलता रहा। मैं उस 2.5 मिलियन टन आइल की प्राइस जानना चाहता हूं। आज जो इंटरनेशनल प्राइस में 15 % की कमी आई है उसका एडवांटेज लिया गया है या नहीं।

एक उदाहरण और देना चाहता हूं। आज हम अन्य देशों को ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कट स्टोन, पालिशु स्टोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी अर्निंग है। इसके लिए रा मटीरियल हम अफ्रीकन कंट्रीज़ से परचेज़ कर रहे हैं।

14.04 hrs.

(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : *in the Chair.*)

रशा यह रा मटीरियल अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है । क्या हम अपने मित्र देश को यह नहीं कह सकते कि वह इस रा मटीरियल को हमें दे ताकि हम फारेन एक्सचेंज बचा सकें? हम रा डायमण्ड परचेज करने के लिए तैयार हैं । इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी ।

इसी प्रकार गोल्ड की स्थिति है गोल्ड के मामले में रशा दुनियां का सबसे बड़ा, दूसरा देश है । क्या हिन्दुस्तान रशा से गोल्ड नहीं ले सकता?

यह जो ट्रेड आफ़ बेलेंस रूपी के आधार पर फेवरेबल है और हम सब्र करके बैठे हैं, वास्तव में यह फेवरेबल नहीं है । में चाहता हूं कि अपने मित्र देश से ऐसी चीजों के लिए कहा जाए जिनसे हम विदेशीमुद्रा अर्जित कर सकें ये चीजं हमको दी जाएं ।

हमारा अधिकतर ट्रेड एग्रीकल्चरल कमर्शियल क्राप्स पर आधारित है । यह भी अधिकतर हमारा रशा के साथ है। आज हमारे यहां टोबेको, माइका, चमड़ा, काजू के व्यापार में कमी आई है, इसको आपने स्वयं स्वीकार किया है। यह व्यापार भी अधिकतर रशा के साथ था । इसी आधार पर हमने इन उद्योगों को डेवलप किया था ।

वहां से रशिया ने अपने आपको विद-ड्रा कर लिया है । क्या यह सत्य नहीं है कि आज राशिया की डिमान्ड कम हो जाने के कारण कच्चा काजू और तैयार काजू गोदामों के अंदर सड़ रहा है ? केरल में कई कारखाने बंद हो गए हैं। और मज़दूर सड़कों पर आ गए हैं। इसका एकमात्र कारण यही रहा कि जो राशिया को हमारा एक्सपोर्ट था, वह बहुत ही कम हो गया । मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में किसी एक मार्किट पर हमें डिपेंडेन्ट नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जल्दी खत्म कीजिए ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हमारी जो बाहर फॉरेन एम्बेसीज़ हैं, वहां ट्रेड के लिए कामर्शियल विंग तो अवश्य है । लेकिन जिस प्रकार का अनुभव हमें हुआ है और आप भी देखते होंगे कि जो कामर्श को डील करने वाले लोग हैं, उनमें इंफीरियोरिटी कांपलेक्स है । आज इस तनावपूर्ण वातावरण में जहां प्रोटेक्शनीज़्म चल रहा है और जहां टैरीफ और नॉन-टैरीफ की बात की जाती है तो ऐसे समय में हमें कामर्श को जानने वाले एक्सपर्ट्स को लगाना चाहिए ताकि जो आज का सेट-अप है, वह ठीक हो सके ।

सभापति महोदय : आपका टाईम हो गया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हमें अपनी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहिए। कई कमेटीज़ की रिपोर्ट आई है कि अगर हम अपनी उत्पादन क्षमता को पूरा कर लें तो लगभग एक हजार करोड़ से अधिक का फॉरेन एक्सचेंज हम बचा सकते हैं । इसी प्रकार अगर हम एनर्जी में आल्टरनेटिव ढूंढ लें तो जिस प्रकार हम फॉरेन-एक्सचेंज या इम्पोर्ट के लिए मजबुर हैं, उससे हम बच सकते हैं । जिस प्रकार से अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कांपलिकेशन्स हो रही

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

हैं उनका मुकावला करके मित्रता के बावजूद भी व्यापारी के नाते प्रेशराइज्ड करके अधिक से अधिक एडवांटेज़ लेने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, उस पर कम से कम इन्टरेस्ट तो डिमान्ड कर सकते हैं। जो कुछ उधार देते हैं उस पर इन्टरेस्ट तो ले सकते हैं। रशिया से क्यों नहीं इन्टरेस्ट लेते ?

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : हमारे वाणिज्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि हम एक ही विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। जैसा कि मंत्री जी स्वयं भी जानते हैं कि किसानों और दस्तकारों द्वारा बनायी जाने वाली चीजों की ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाना चाहिए। इससे उन लोगों को काम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी तथा जीवन-स्तर भी ऊंचा हो जायेगा।

मेरे क्षेत्र मिर्जा-भदोही में वाणिज्य मंत्री जी ने कालीन उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया है। वहां काई लाख लोग कालीन का काम करते हैं। मेरा ख्याल है पूरे भारत वर्ष से जितना कालीन का निर्यात होता है, उसका 70-75 प्रतिशत भाग केवल मेरे क्षेत्र से होता है। जो आंकड़ें मुझे मिले हैं उसके अनुसार 1977-78 में कालीन का 83.7 करोड़ रूपए का निर्यात हुआ था। फिर, 1981-82 में बढ़कर 173.7 करोड़ का हो गया। लेकिन 1982-83 में फिर घट गया और 87.19 करोड़ ही रह गया। 1977 की तुलना में 26 पाइन्ट की बढ़ोत्तरी तो हुई लेकिन जितना निर्यात होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है।उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। कालीन के उत्पादन को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। असल में कंपीटीशन ज्यादा हो गया है। कालीन के निर्माण के संबंध में इस समय मुख्य प्रतियोगिता पाकिस्तान और चीन से है। कुछ और देश जैसे ईरान, कोरिया, ताईवान और थाईलैंड भी इसमें आ गए हैं। जब कई मुल्क इस प्रतिद्वन्द्विता में आ गए हैं तो कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा।

वाणिज्य मंत्री की विशेष ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने पहले ही खुद विशेष ध्यान दे कर इस उद्योग को बढ़ावा दिया है। पुन: इस और ध्यान देने की आवश्यकता इस समय आ गई है। यह उद्योग ऐमप्लायमेंट ओरियेन्टेड है, कई लाख लोग गांवों में इस उद्योग में लगे हुए हैं जिससे पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती है, दूसरे यह उद्योग ऐक्सपोर्ट ओरियेन्टेड भी है। तो इसको कई तरह से बढ़ावा देना अति आवश्यक है। इसके लिये में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले हमारा देश कालीन के निर्यात के मामले में दूसरे नम्बर पर था, लेकिन अब पाकिस्तान दूसरे नम्बर पर आ गया है और वहां इस को बढ़ावा देने के लिये बहुत सी फेसिलिटीज़ दी जा रही हैं। 7 परसेंट छूट पर ऋण दिया जाता है, वितरण की मारकेटिंग की सूविधा ज्यादा दी जाती है। इंसेंटिव जो 3 परसेंट घटा दिया गया है वहां भी वह दिया जाता है, इसी तरह से और देशों में भी होता है। अत: जब इस उद्योग में कम्पटीशन है, लोगों को रोजगार मिलता है तो इसको बढ़ावा देने के लिये कुछ हमारे सुझाव हैं जो में गिना देना चाहता हूं। एक तो कैश इंसेंटिव पहले 20 परसेंट दिया जाता था, अब 3 परसेंट घटा दिया गया है इससे इस उद्योग को बहुत धक्का लगा है। हमने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री को कहा, वर्तमान मंत्री जी ने तो जा कर देखा है, इनकी कृपा से यह उद्योग बढ़ा भी है, तो इंसेंटिव कुछ और बढ़ा सकें तो बढ़ाया जाय। दूसरे यह कि कालीन उद्योग के लिए कारपेट फ़ाइनेंस कोरपोरेशन

अलग से बना दिया जाय जो कालीन वालों को लोन दे और उद्योग को बढ़ावा दे। तीसरा सुझाव यह है कि जैसे पाकिस्तान आदि देशों में कमइंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है वैसे ही यहां भी दिया जाय। भुगतान में कभी देर हो जाती है, जैसे जर्मनी या जापान में भुगतान फंस जाता है तो इसकी तरफ़ भी आपको ध्यान देना चाहिये कि भुगतान न रुके। कुछ ऐसे कालीन के व्यपारी इस व्यवसाय में आ गये हैं जो कालीन नहीं बनाते हैं, केवल कालीन खरीद लेते हैं रद्दी माल खरीद् लेते हैं और फिर उसको विदेशों में बेजते हैं जिससे विदेशों में हमारे कालीन की क्वालिटी लोगों की निगाह में गिरती है और हमारा कालीन खराब माना जाता है। इसलिए इस तरह के जो व्यापारी आ गये हैं जो केवल कारपेट ही खरीद लेते हैं उनको रोक लगानी चाहिये। जो मेनुफेक्चरर्स ऐक्सपोर्टर्स हैं ऊन्हीं को बढ़ावा दिया जाय।

भदोही और मिर्जापुर के एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया मान कर के पूरे समय बिजली दी जाय और मशीन मेड कालीन पर जो इंसेन्टिव दिया जाता है उसको न दे कर हाथ से बनाने वालों को इंसेंटिव दिया जाया जो कालीन एरियाज़ हैं उनको लिंक रोड से जोड़ा जाय। इंस्टीट्यूट आफ़ कारपेट टैक्नालाजी की आपने मंजूरी दी थी, उसके लिये ज़मीन भी ऐक्वायर कर ली गई है, मगर काम आगे नहीं बढ़ा है, उस पर आप ध्यान दें, इससे लोगों को काम मिल जायगा और नए नए डिज़ाइन जानने का लोगों को मौका मिलेगा। कोयला कालीन उद्योग वालों को ब्लैक में खरीदना पड़ता है। इसलिये इस इलाके के लोगों ने जो कोआपरेटिव सोसायटी बनायी है उसको कोल इंडिया से सीधे कोयला दिलवाने की व्यवस्था की जाय जिससे उचित दाम पर कालीन उद्योग वालों को कोयला मिल सके भदोही वूलन मिल का विस्तार किया जाय और एक और वूलन मिल मेरे इलाके में खोली जाय। बुनकरों के कल्याण के लिये कुछ इंतजाम किया जाय और इस विशेष क्षेत्र में कई लाख कालीन उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं तो कालीन मजदूर कल्याण परिषद् के नाम से एक संस्था चलायी जाय।

हमारे मिर्जापुर का बर्तन उद्योग बहुत पुराना उद्योग है, हजारों लोग इसमें काम करते हैं। मंत्री जी वहां के लोगों की कठिनाइयों को जानते हैं। वहां कुछ नई टैक्नोलाजी देकर, इन्सेंटिव देकर अगर वहां बर्तन उद्योग को बढ़ाया जायेगा तो मिर्जापुर शहर उजड़ने से बच जायेगा।

अन्त में इस मंत्रालय की मांगों का हम समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि क्योंकि मंत्री जी वहां की कठिनाइयों को जानते हैं, वे इस बारे में अवश्य ध्यान देंगे।

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): Sir, on behalf of DMK Party I rise to support the demands for grants of the Ministry of Commerce and the Deparment of Supply.

The Controlled cloth supplied at present requires much to be improved in its quality to attract the people to buy it in huge quantity, I want to bring to the notice of this august House the fate of the employees working in the show-rooms of the National Textile Corporation all over India, their service conditions, pay, etc. They were agitating for the betterment of their service conditions for some months last year It was withdrawn a few months back on certain assurances I request the Hon. Minister to look into their demands favourably and accept their demands in toto, as they are all just demands and Government, as a model employer, has to conform to its ownlabour laws and regulations. I hope it will be done early so that the employees in the N.T.C. showrooms work with

[Dr. A. Kalanidhi]

satisfaction in their job and serve the nation with more vigour.

As far as the Handloom sector is concerned, I have to emphasise that no amount of subsidy given will serve this industry to the extent needed. It can be ensured only by the uninterrupted supply of yarn, to the required demand at a steady price and by reserving cotton sarees and dhoties with borders entirely to the Handloom sector. Only this arrangement will ensure the growth of this sector and could be a viable industry standing on its own legs. This type of reservation of certain categories of cloth to the handloom sector was sought for by my party founder Arigna, ANNA, Years ago. Yet the Government of India has not even given any thought over this suggestion. I request the Hon. Minister to think over this and do the needful in right earnest to alleviate the sufferings of the workers in the Handloom industry and allow them to lead a peaceful life, not only to their satisfaction, but also to the satisfaction of the people in India. Let the National Cooperative Development Corporation and the Handloom Development Corporation proposed to be set up in this year, undertake to supply yarn required by the Handloom industry at a fixed price throughout the year without any interruption in the supply all over India.

It is seen from the notes in the Demands of this Ministry, that the Trade Fair Authority of India has organised an international Trade Fair at New Delhi in November, 1982 I see that such trade fairs are always held at New Delhi only. I have to state that such trade fairs are not held in any other part of India. I request the Hon. Minister to arrange to hold such international trade fairs at least in the State capitals. India should not be viewed as only New Delhi by foreign nations. They should also know that there are number of places in India, developing rapidly, competing with the other nations in the world.

The Kandla Port Free Trade Zone was set up in 1965. Huge amount was spent in this area in the past. Yet, the total exports from this zone during 1982-83 will be only 120 crores. The progress and achievements from this Free Trade Zone is not up to the mark and it requires to be improved at least to the extent of the expenditure incurred already. In this connection I request the Hon. Minister to finalise early the proposals to open a free trade zone near Madras City either at Meenambakkam Air Port or at Manali industrial complex. Let us have the free trade zone in Tamil Nadu, and I hope it will function very well, more than the expected growth by the Ministry. Let Tamil Nadu have it not for the benefit of my State, but also for the benefit of our nation.

The Marine Products export Development Authority which is looking after the development and regulation of the Marine Products Industry with special reference to Exports has not done anything substantial to Tamil Nadu, which has the longest coast in India. I request the Hon. Minister to do the needful in this regard so that this Corporation concentrates much in Tamil Nadu to enable the fishermen to be benefited.

The Bharat Leather Corporation is not functioning well, as is known to me, from the reports received from the public. The Officials in this Corporation are indulging in all sorts of illegal activities and adopt methods leading to heavy loss to Government. The purpose for which the Corporation has been formed is not understood by the officials of this Corporation and the policies of the Govt. are not implemented in true spirit.

I hope the hon. Minister will look into these, and take suitable and effective action to make this Corporation function true to its objectives and aims.

The Bharat Leather Corporation is at present procuring snake skins from private trades and gives it to certain agencies to convert them into various articles to be exported. The snake skins seized by Customs are being taken over by the Corporation, besides the snake skins under the custody of the private trades This Corporation asks the private traders to give the snake skins to them, at throw-away rates. This Corporation gives the snake skins to certain vested

persons at cheaper prices, and gets back inferior articles manufactured by them. The huge quantity of snake skins held by this Corporation is actually unsafe and misappropriated. It is suggested that the snake skins legally procured by the private traders be allowed to be converted into articles by themselves, to be exported by Bharat Leather Corporation. This will encourage the small scale industry and make available employment to many poor cobblers, traders etc. This will also eliminate the malpractices indulged in by the officials of the Bharat Leather Corporation, and harassment of the private traders by the Customs and Wild Life officials also. I hope the hon. Minister will do the needful in this regard.

You have banned the cobra skins and python skins. I can appreciate that; it was legitimate. But at the same time, you have also banned the skins of 'whips' which we call 'Saarai Pambu' in Tamil, and the water snakes which we call 'Thanneer Pambu' in Tamil. But these are harmless snakes. So, Government should take steps to remove the ban on catching these snakes. The people who catch these snakes are poor and down-trodden ones, and they belong to minority communities.

The soda ash and viscose fibres are being imported freely, to the detriment of the indigenous industry. Recently, the excise duty on the imported goods in these categories has been raised, but the imported price has been suitably lowered—than that of the indigenous products. Why is such a policy being followed ? Our own industry is suffering by this kind of unrestricted imports. When there is demand, and where we could produce these products by ourselves, what is the need for imports ? Why could not the price be fixed at a lesser rate ? How can we substitute the imports ?

Before concluding my speech, I wish to raise the following questions : (1) Has the State Trading Corporation of India imported 10,000 tonnes of soda ash in 1981 from Bulgaria ? (2) Has STC reduced the price from Rs. 2,250/-per tonne to Rs. 1,800/-per tonne, since they could not sell it ? (3) Is it a fact that STC is still having the stock; and (4) What is the total loss to the Exchequer on account of reduction in price, including rent, interest, insurance and administrative expenses ?

In the recently announced Import Policy, soda ash has been taken out of the open General Licence. This action should have been taken long back. However, this has been done now. I thank the hon. Minister for this action.

Regarding the Department of Supply, I have to state that DG S&D has to inspect the supply made by the factories to various Government departments, and ensure that they keep up the terms and conditions of the rate contract. The cement bags released from the factories are not only up to the I.S., standards, but also less than the stipulated quantity; they allow 2% as tolerance limit. Why should it be allowed-is a mystery. Why could not the factories ensure correct weight at the time of supply ? Why should DG S&D not ensure correct weight ? Certain factories, taking advantage of this tolerance limit, actually weigh the bags less than the stipulated 50 kgs. per bag. The standard of quality of cement manufactured in India is far less than the quality of imported cement. This might be due to difference in the standards stipulated by ISS and BSS. Why cannot the standards of ISS be fixed on par with BSS ?

It is seen the Shipping and Clearance Service rendered by a wing of this department at Madras, Calcutta, Bombay, etc. ports can be expanded to cater to the needs of other organisations including the Shipping Corporation of India, in view of the fact that the Shipping Corporation of India says that such a shipping and clearance service is not a profitable one. Moreover, the service done this wing at Madras Port is only two contracts in 1981-82, 1982-83 and proposed for 1983-84 also, where as the tonnage import has risen from 55,000 to 75,000. Some efforts should be made in right earnest to improve the functioning of this wing to attain a higher growth rate, in handling the tonnage export and import.

With these words, I conclude.

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबे आली, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे पहले बोलने के लिए टाइम दे दिया।

जहां तक ट्रेड ऐंड कामर्स मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, में इस मिनिस्ट्री और खास तौर से मिनस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे मुलक पर जो एक बहुत बड़ा बौझ है ओर था, जो बाहर से हम तेल मंगवा रहे थे जिसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थीं और उसको लाने से हसरे देशका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, उसको कम करने की कोशिश इन्होने की है और बहुत कामयाबी से की है 1980-81 में जो 5850 करोड़ का डेफिसिट था, उसको 1981-82 में 5837 करोड़ पर स्टैबलाइज़ कर दिया। 1982 के पहले 9 महीनों में उसको 4060 करोड़ तक ले आए जोकि पिछले इसी पीरियड के मुकाबले में लोयस था। इस तरह से उन्होंने डेफिसिट को कम किया।

इसके साथ साथ जहां तक हमारी एक्सपोर्टस का ताल्लुक है, 1980-81 में 3.9 परसेन्ट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, 1981-82 में 16.3 परसेन्ट बढ़ा और 1982-83 में 15.1 परसेन्ट बढ़ा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मिनिस्टर साहब ने काफी मेहनत की है इसलिए वे दाद के मुस्तहक हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि 1982-83 में 9000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा जबकि 1981-82 में वह सिर्फ 7802 करोड़ का ही था प्रोसेस्ड फूड, काटन टेक्सटाइल और दूसरी मुख्तलिफ चीजों को बाहर भेजकर हमारे मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ाया गया है। थर्ड वर्ल्ड के डेवलपिंग कन्ट्रीज़ और नानएलाइन्ड कन्ट्रीज़ को हमारे मुल्क की तरफ से मदद भी की जा रही है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और दुनिया में एकोनामिक स्टैबिलिटी आ सके। आज दुनिया में जो एकोनामिक क्राइसिस चल रही है उसके बावजूद इस मिनिस्ट्री ने हमारे देश की फारेन और इन्टर्नल ट्रेड को आगे बढ़ाया है।

थर्ड वल्ड कन्ट्रीज़ में एकोनामिक क्राइसिस है उसपर भी काबू पाना है। यह भी ज़रूरी है कि उन मूल्कों को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए हमारी तरफ से कोशिश भी हो रही है। इस मिनिस्ट्री के जरिए से और बाहर जो मुख्तलिफ इरादे हैं, वहां पर हमारे मिनिस्टर साहब खुद जाकर हिस्सा ले रहे हैं या मिनिस्ट्री के आफीसर्स जा रहे हैं। ज्वाइन्ट वेन्चर्स के जरिए से भी काम किया जा रहा है। हवाई जहाज़ के अड्डे, बिल्डिंग्ज़, हास्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्ज़ को बनाने में मदद दी जा रही है। टेक्निकल नो-हाऊ और माली मदद भी दी जा रही है। ज्वाइन्ट वैन्चर्स के जरिए से भी काम कर रहे हैं।

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1981-82 में उसने 555 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 1982-83 में 647 करोड़ का किया और 1983-84 में 762 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रोजेक्टेड है। फुटवीयर, टेक्सटाइल गार्मेन्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। एक बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहाँतक लेदर टेक्नोलाजी का सवाल है, मैंने मद्रास में सेन्टर देखा है, लेदर टैक्नोलाजी में हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। किसी ज़माने में हमारी लेदर फुटवीयर की ट्रेड बहुत अच्छी थी।

प्राइवेट सैक्टर में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं मास्को गया था, तो वहां एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कार्पोरेशन के चेयरमैन ने मुझ से कहा

'We imported black shoes but when we got them they were green shoes'.

इन बातों को हमें रोकना चाहिए। क्वालिटी कन्ट्रोल निहायत जरूरी है। टैक्सटाइल के अंदर ही नहीं, बल्कि दूसरी चीजों में भी। एस.टी.सी. की एफीशियेंसी क्वालिटी कन्ट्रोल में नीचे आ रही है। फ्री-ट्रेड जोन कांडला में कायम किया है। वहां अच्छा काम हो रहा है। मैं पॉलिशी के तौर पर मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जब तक ट्रेड का डामैस्टिक बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक फॉरन-ट्रेड जिन्दा नहीं रह सकती है। किसी वक्त 50 कंसीड्रेशन्स सामने आजाती हैं। हमें किन शर्तों पर सामान को लेना है, वे आपको कबूल है या नहीं है, इन सबको देखते हुए सबसे पहले आपको अपने घर का डामैस्टिक फ्रण्ट मजबूत करना होगा। आप एक्सपोर्ट के लिए प्रोजैक्ट्स बना रहे हैं, उसके लिए आपको पोर्ट-मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ को डवेलप करना होगा। हमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देकर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। हम इसे अच्छे किस्म का काम करें, जिससे हमारे मुल्कका प्रोडक्शन बढ़े, एम्पलायमेंट बढ़े। खास कर के जो हमारे ट्रेडिशनल्स ट्रेड्स है, जैसे हैण्डीक्राफ्ट और निटवीयर, जिससे हमारे लोगों को काम काज मिलसकता है इस ओर भी काम करना चाहिए।

एक बात में आपको और कहना चाहता हूं। आपका ट्रेड कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि आप तीनों सैक्टरों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्राइवेट सैक्टर में मैंने देखा है कि वह सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, बहुत सी चालाकियां कर रहा है। टैक्नालाजी इम्पोर्ट करने के नाम पर कभी किसी चीज़ के नाम पर। प्राइवेट सैक्टर में टैक्नालाजी या कोई और चीज़ के नाम पर विदेश से कर्जा लेते हैं। मैंने देखा है कि 33 हाउसेस ऐसे हैं, जो विदेशों से कॉमर्शियल बॉरोइंग कर रहे हैं और 90 के करीब ऐसे Supplier Credit ले रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट आफ इन्डिया की गारन्टी नहीं है, रिजर्व बैंक की गारन्टी नहीं है सिर्फ इजाजत ही लेते हैं। जब तक कर्जा देने वाले को फायदा न हो और रिस्क न हो कौन बिदेशों में कर्जा देगा। अच्छी तरह से इन बातों को देख लेना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर ही नहीं को-ओपरेटिव सैक्टर को भी बढ़ाना चाहिए। खास कर इन्डस्ट्रीयल को-ओपरेटिव सैक्टर और दूसरे को-ओपरेटिव सैक्टर की ओर आपको ध्यान देना चाहिए और स्पेशियल एफर्ट करने चाहिए।

आपने कुछ कन्सैशन्स दिए हैं, इन्सैन्टिव दिए हैं स्माल स्केल सैक्टर और को-ओपरेटिव सैक्टर को तरजीह देनी चाहिए। को-ओपरेटिव सैक्टर को बल्कि ज्यादा इन्सैन्टिवज देने चाहिए। स्माल स्केल सैक्टर में लार्ज और मिडिल सैक्टर को सिर्फ इन्कम टैक्स में रियायत देनी चाहिए। इसकी तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिए जो इन्सैन्टिव दिए, वे भी विद-ड्रा कर लिए हैं, इस पर आपको दोबारा सोचना चाहिए। इस की वजह से स्माल स्केल सैक्टर और को-ओपरेटिव सैक्टर हार्ड-हिट हुए है।

कीओपरेटिव सैक्टर का खास तौर पर कहा जाता है कि स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज के लेविल पर आ जाओ, तो एक्सपोर्ट कन्सेशन मिलेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं और मिनिस्टर साहब भी इस बात को जानते हैं कि कोओपरेटिव सेक्टर में जो गरीब आटीशन्स हैं, उन को ही कोओपरेटिव सोसाइटी रेप्रेजैन्ट करती है। इसलिए डेवलपमेंट कमिश्नर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, उन को कोओपरेटिव सेक्टर वाले इंदारों कोओपरेटिव एक्सपोर्ट हाऊसेज और स्माल

(श्री गिरधारी लाल डोगरा)

स्केल इन्डस्टियल एक्सपोर्ट हाउसेज उन के एट पार बरताव नहीं करना चाहिए बल्कि उन (Cooperative export-Houses) को Small Scale Industrial export-Houses. से ज्यादा फैसिलीटीज देनी चाहिए क्योंकि वे वीकर सेक्टर को रेप्रेजेन्ट करते हैं और उन में उन का अपना कोई पसर्नल इन्ट्रेस्ट नहीं होता है। इसलिए उन को ज्यादा वेनीफिट्स देने चाहिए और कोओपरेटिव एक्सपोर्ट हाउसेज की तरफ़ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सेन्ट्रल रजिस्ट्रार आफ़ कोओपरेटिव्ज की रजिस्ट्रेशन के मामले में वनिस्वत डेवलपमेंट कमिश्नर आफ़ स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।

अब जहां तक चाय का ताल्लुक है, और काफी का ताल्लुक है, इन का कम्पीटीशन मल्टी-नेशनल कम्पनियों के साथ है खास कर बूकबोंड और लिप्टन कम्पनियों से है। मैं ने बाहर जा कर देखा है कि इन के साथ ज़्यादा कम्पीटीशन है। इस में आप का जो टी बोर्ड है और टी कारपोरेशन है, वे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एन. एफ. आई. सी. जैसे जो अदारे हैं, जो बाहर टी फ्रोत्स्य कर रहे हैं, उन को इन्सेन्टिव देना चाहिए ताकि चाय जो है वह बाहर जा सके और लोगों के मुहं में यह जा सके। अगर लोग इस को पीने लगते हैं, तो एक चस्का उन को लग जाएगा और फिर मार्केट को एक्सप्लायट किया जा सकता है। स्केन्डीनेवियन कन्ट्रीज में हामरी चाय काफी को डिस्प्लेस कर रही है। एक दफ़ा टी वहां चली जाएगी और उस को बहां पर बेचेगें तो मार्केट को कप्चर किया जा सकता है और एक दफ़ा और मार्केट केप्चर हो जाता है, तो फिर जैसा चाहें, वैसा कर सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसमें कोओपरेटिव सैक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। इसको ग्रो करने के लिए, इसको सेल करने के लिए और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्माल और मार्जीनल फारमर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए।

हैन्डीक्राफ्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, इस में सरकार को हैन्डीक्राफ्ट्स के ट्रल्स को माड्रेनाइज कराना चाहिए। हैन्डीक्राफ्ट्स सिवाय कोओपरेटिव्ज़ के और दूसरे सेक्टर में नहीं चलेगा। इसी तरह से कारपेट्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए मगर इसमें प्राइवेट सेक्टर की बजाय आर्टीशन्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। मैंने अपनी स्टेट में इनकी कोओपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ाबा देने के लिए काम किया है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इनको एक्सपोर्ट करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। इसलिए कोओपरेटिव सैक्टर में जो एक्स-पोर्ट हाऊसेज हैं, उनके द्वारा इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

वूल और वूलन्स के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि हमारे यहां जो वुल पैदा होती है, हिमाचल प्रदेश में और हमारे यहाँ जो वूल पैदा होती है, वह आस्ट्रेलिया की वूल से क्वालिटी में कम नहीं है, उसके बराबर ही है लेकिन हो यह रहा है कि उसको मिक्स करके प्राइवेट सेक्टर वाले गारमेंट्म की क्वालिटी को खराब करते हैं। इस चीज़ की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए।

एक आखरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। एस०टी०सी० को एडीविल आयल का डिपो हर स्टेट के अन्दर खोलना चाहिए। चन्द स्टेट्स में यह है और चन्द में नहीं है। 4 पर सेन्ट इस में टैक्स पड़ जाता है और 4 परसेंट

का मतलब यह है कि 10-12 परसेंट ज्यादा में जाकर वह फ्रोस्ट होता है, जिसका असर गरीब आदमियों पर पड़ता है। मेरी स्टेट जे० एण्ड के० में कोई डिपो नहीं है, और एस० टी०सी० को यह डिपो, खुलवाना चाहिए। बाकी जो दूसरी बातें मैंने कही हैं, उन पर मंत्री महोदय ध्यान । दें

PROF. P. J. KURIEN (Mavelikara) : I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Commerce. This Ministry is the pivotal Ministry as it deals with the foreign trade, which is very important with regard to the economic and industrial development of our country.

The foreign trade has two important parts-export and import. The success and failure of this Ministry can be evaluated by examining the effort put in by the Ministry, in expanding the foreign trade and reducing our import bill. Viewing from this angle I feel that though we are not completely out of woods, there is every reason for the hon. Minister and the Ministry to be proud of. When we view the performance of the Ministry, we should bear in mind the world situation with regard to trade. The Ministry of Commerce in its Report has said :

> "The world trade and economic situation has been steadily deteriorating in recent years as a result of which the developing countries are being worst hit, According to available data the world production grew only by 1 per cent in 1981, even lower than the performance in 1980.....The value of world trade in 1981 at nearly doller 2000 billion was 1 per cent less in 1980 and in volume terms the world trade in 1981 stagnated."

It is in this sluggish world trade background that we have to examine the performance of this Ministry, I am very happy to say that in spite of this discouraging trend in the world trade the Ministry has made advance and its efforts have yielded wonderful results.

Sir, according to the Report, our exports in the year 1981-82 increased to the tune of 16.3 per cent, which was only 3.9 per cent in the previous year, i.e., 1980-81. Similarly, during the first nine months of 1982-83 our exports increased by 15.1 per cent over the exports of the corresponding period last year. This is a commendable achievement and I hope the Ministry will be able to keep up this boyaney in our exports.

Another welcome trend which I see is with regard to the reduction in the import bill. Over the years our import bill was going up and up, but it is a welcome sign that the Ministry is able to bring down the burden and our import bill is found to be on the downward trend. In 1979-80 our import has gone up to 34.2 per cent and in 1980-81 it had further gone up to 37.4 per cent. This increase in the import has created a peculiar situation. We were forced to take loan from the IMF. However, in 1982 it is a remarkable and happy thing to note that the increase in our import bill was brought down from a staggering 37.4 per cent to 8 per cent. Thus, when we see we find considerable increase on the export side, at the same time reduction in the import bill. This is a welcome trend and for this I congratulate the Ministry.

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : Thank you.

PROF. P. J. KURIEN : But I am coming to some other points also.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude. Already five minutes are over, another two minutes only are left.

PROF. P. J. KURIEN : Sir, a number of measures are taken for import substitution and I do not want to mention them here. We are making an effort in the domestic field to produce more oil. I feel that this break through in oil production will definitely have a direct impact on our import bill and I hope our import bill will further reduce.

Going through the Report, I notice that during 1982-83 the export performance with regard to items like marine products, tobacco,

(Prof. P. J. Kurien)

processed food, engineering goods, chemicals etc. is better, but at the same time I would say that in respect of cashew, leather, woollens etc, the performance suffered a setback.

PROF. N. G. RANGA : Jute also.

PROF. P. J. KURIEN : Of course, jute also. This setback has affected our industry, especially with regard to cashew it has affected Kerala and Tamil Nadu. I will refer to it later on.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : If you don't conclude, I will call the next speaker.

PROF. P. J. KURIEN : How minutes have I taken ?

MR. CHAIRMAN : About five minutes.

PROF. P. J. KURIEN : You tell me, how much time you are giving so that I will stick to it.

MR. CHAIRMAN : You have taken five minutes. You have only two minutes left.

PROF. P. J. KURIEN : Only five minutes ? I thought you are giving me 10 minutes.

MR. CHAIRMAN : I am not giving 10 minutes.

PROF. P. J. KURIEN : Please give me the time you have taken now.

MR. CHAIRMAN : You are unnecessarily wasting time. There are 14 more speakers. Then what to do ?

PROF. P. J. KURIEN : I am elected from Ketala. I am a Member of parliament representing a constituency in Kerala.

MR. CHAIRMAN : But you are not speaking about Kerala.

(*Interruptions*)

PROF. P. J. KURIEN : I agree, Sir, You can control me, but don't say how I should speak.

MR. CHAIRMAN : Speak about Kerala. Why don't you speak about Kerala ?

PROF. P. J. KURIEN : Thank you. I will speak about Kerala. I thought I will have a general review and then come to Kerala because if I could give the good side, then only I can give the other side.

With regard to Kerala I have to say about the import policy announced this year. In the import policy I find that most of the cash crops produced in Kerala are allowed to be imported on OGL. This is very much detimentally affecting the industry and the growers in Kerala. With regard to rubber, the hon. Minister has already said something, but I feel it should be examined. My feeling is that we are producing enough rubber required by our industry. The position is that to fill a small gap when they import, that will have an impact on production. Again with regard to cocount oil and nutmeg and other things, the import is adversely affecting the industry and also the people of Kerala. I have only one request to the Minister and that is that the import of rubber, coconut oil and nutmeg should be re-considered and even if you allow some quantities of these items, you should do it only after careful examination and assessment. This is one request.

Another point is about cashew nuts about which already a mention has been made. Last year the Soviet Union purchased 21,000 tonnes of cashew from us and this year they have not purchased anything so far. I know all the efforts you are making. But what is the position now ? Two lakhs of employees in Kerala and Tamil Nadu are starving and the growers are not getting proper price. Last year there was monopoly procurement, but this year there is no monopoly procurement. The growers are at a loss, the workers are starving and nearly 25,000 tonnes of cashew are lying idle. Our main buyer is the Soviet Union. I do not know why they have withdrawn from purchasing from us this year. As the Soviet Union is a friendly country, I hope the Ministry will be

able to persuade them to buy the cashew which we are having.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Only from India.

PROF. P.J. KURIEN : Yes, from India. I know their problem. They are buying from some other country. Whether it is a rupee problem or some other problem, I am not concerned. But if it is not taken up seriously, two lakhs of workers in the field would be starving. This is what I have to say and I request the Ministry to take it up seriously.

Another point is about merine products. As I have already said, in respect of marine products export, we have gone beyond the target and I am happy about it. But I have to say one thing in this regard. Much has to be tapped in this field.

It is a vast resource but we are not even tapping some percentage of it. That is my grievance. We have 200 miles exclusive zone and vast sea coast. Take Taiwan. They have 7,000 trawlers. Japan is having 14,000 trawlers. We are having such a vast sea coast and economic zone but we have only 57 trawlers. I would request that special effort should be made in deep sea fishing because that will increase our export earning. Commerce Ministry should not hesitate to import technically superior quality trawlers and our young men should be encouraged to go for deep sea fishing. I am not favouring chartering or joint ventures.

Last year in 1982, C.A.G. has said about chartering and joint ventures. He said that it is not in the interest of the country. I quote :

> "The procurement of trawlers under joint ventures and charters did neither help in speedy import nor in indigenous construction of trawlers as envisaged. Further, the unit value realisation per kg. of exports by the chartered vessels range from Rs. 2.28 to Rs. 5.38 only against the unit value realisation of Rs. 7.74 to Rs. 15.40 kg from exports of the same variety of fresh fish to other countries. Due to this, there was a loss of foreign exchange earning of about Rs. 6.85 crores".

What I said was that we should encourage deep sea fishing and our own people to go in for deep sea fishing. At the same time we should not encourage joint venture and chartering because that is detrimental to our national interest.

In a nut shell I have to make a request regarding cashew. Unless you do something 2 lakh people will be starving to death in Kerala.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : I am referring to National Jute Manufacturing Corporation. This is a nationalised undertaking consisting of six nationalised jute mills. I do not know who is the real patron-starting from Shri Pranab Mukherjee, then Shri Shivraj Patil and now Shri Vishwanath Pratap Singh. Nobody seems to be inclined to take any action or even concerned to take any action with regard to these mills. I have written numerous letters. I must confess that the Central Ministers are very prompt and courteous in at least giving acknowledgment and reply to letters from M.Ps. But so far as NJMC is concerned, it seems to be an exception. Nobody seems to answer even.

Service conditions have not been farmed, although nationalisation has taken place. There is a rumour that service conditions are being framed and are going to be imposed on the employees and the staff. But no consultation has taken place with single union. There is a federation of NJMC Staff Associations. I happen to be the President. Staff Associations of the five mills out of six are Member of this Federation. They are not taking any note of it. I have sent telegram to the Minister. Probably he was out on foreign tour. There is no response to that. No action has been taken. I would request to him hold some consulation with the employees association in regard to service conditions or if you unilaterally

(Shri Somnath Chatterjee)

frame and thrust them upon employees then there will be resistance.

Secondly I want to say something about industrial relations. This federation is representing 90% of the officers and staff. We are not even being taken notice of. Our letters are not acknowledged by the management. They say we can talk to you Mr. Chatterjee as a Member of Parliament but not as the President of the Federation. This is the attitude of the management. They say that. I do not understand. Is this the way Government Undertakings, Central Public Undertakings or any public sector undertaking will behave ?

15.00 hrs.

Will they not take note of the existence of the association which is representing the majority of the employees ? (*Interruptions.*) There is another thing which I want to mention here. Unfortunately, this corporation continues to be full of corruption. I am sure, Mr. Sangma will bear me out. Many times, I have brought to the notice of the Ministry such instances and I want to know what action has been taken in this regard ?

Mr. Chairman, I am obliged to you for giving me this time and opportunity.

MR. CHAIRMAN : Now, the Home Minister to make a statement.

15.00 hrs.

STATEMENT RE INCIDENT AT AMRITSAR ON 25th APRIL, 1983

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, It is with great sense of sorrow and anguish I have to inform this House the murder of Shri A.S. Atwal, Deputy Inspector General of Police, Jullundar at 11.10 A.M. yesterday while he was visiting Darbar Saheb, Amritsar for offering prayers. According to information received from the Government of Punjab, he was shot dead just outside the main entrance of Darbar Saheb towards Chowk Ghanta Ghar at Amritsar. He was reportedly fired upon by one unidentified Sikh youngman while he was coming outside from Darbar Saheb after paying homage to Sri Guru Granth Sahib. The assailant had reportedly come from inside the Darbar Saheb complex with rifle and reportedly ran back to the Darbar Saheb after committing the crime. Varinderjit Singh, a young boy of about eleven years and Kulwinder Singh, resident of Amritsar were also injured and removed to Hospital. While the former succumbed to his injury, the latter is lying in serious condition. The information regarding wanted criminals, including Dal Khalsa activists, taking shelter in places of worship, that the Government have been receiving from time to time is confirmed by the destardly crime near the Darbar Saheb itself. All Senior Superintendents of Police in Punjab have been alerted and Director General of Police has rushed to the spot. The request of State authorities to the SGPC to handover the accused person has not been heeded to so far.

Government has decided to entrust investigation of this case to the C.B.I. and Director, C.B.I. himself is proceeding to Punjab.

As the House is aware, I had appealed to all concerned to shun violence and ensure that the places of worship are not used for inciting violence. Honourable Members have also expressed similer sentiments. It is unfortunate that this appeal has gone unheeded.

The Government has been making earnest efforts to sort out various issues. Honourable Members will agree that such incidents and violent activities do not help in finding out a solution.

I am confident that the House will join me in appealing to all concerned particularly the leadership of Shiromani Akali Dal and SGPC to see that such violent incidents involving loss of innocent lives do not recur.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Sir, may I request that we all condole the death of this brave and valiant officer and condemn the manner in which the above officer was